



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, वीरवार, 20 दिसम्बर, 2001/29 अग्रहायण, 1923

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 20 दिसम्बर, 2001

संख्या 1-76/2001-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 (2001 का

बिधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,  
सचिव।



2001 का विधेयक संख्यांक 21.

## हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001 है।

संक्षिप्त नाम।

1994 का  
12

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में, विद्यमान खण्ड (14) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा :—

धारा 2 का संशोधन।

"(14) "राजस्व आयुक्त" से, हिमाचल प्रदेश का राजस्व आयुक्त अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन राजस्व आयुक्त के सभी या किन्हीं कृत्यों के पालन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी इसके अन्तर्गत है;"।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 की, उप धारा (2) में,—

धारा 8 का संशोधन।

(क) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ घ) यदि उसने धारा 13-क के अधीन विहित से अधिक व्यय उपगत किया है या निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के तीस दिन के भीतर, धारा 13-ख के अधीन लेखा जमा करने में असफल रहता है;"

(ख) खण्ड (ङ) में "किसी अपराध में", शब्दों के पश्चात् और "दोषसिद्ध ठहराया गया है" शब्दों से पूर्व, "दण्ड न्यायालय द्वारा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण.—"नैतिक अधमता" से, ऐसे मामले अभिप्रेत हैं, जहां सक्षम न्यायालय द्वारा विरचित आरोप वाले अपराध जिनके लिए अधिकतम दण्डादेश, मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक कारावास अन्तर्बलित है;"



(घ) खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (थ) और (द) जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

“(थ) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है:

परन्तु खण्ड (थ) के अधीन निरर्हता, उस व्यक्ति को जिसके, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारम्भ होने की तारीख से, या ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं, तब तक लागू नहीं होगी, जब तक एक वर्ष की उक्त अवधि के पश्चात् उसके और सन्तान नहीं होती; और

(द) यदि उसने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन, कोई मिथ्या कथन या घोषणा की है।”।

धारा 9 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में, “राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृन्द” शब्दों के पश्चात् किन्तु “उपलब्ध कराएगा” शब्दों से पूर्व, “सामग्री और आर्थिक साधन” विन्हु और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9-क, 9-ख, 9-ग, 9-घ और 9-ङ, का अन्तःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“9 क. परिसरों, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोग के लिए अधिग्रहण.—(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि नगर निगम के सम्बन्ध में,—

(क) मतदान केन्द्र के रूप में या मतदान होने के पश्चात्, मतपेटियों को रखने के लिए, उपयोग करने के प्रयोजन हेतु, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सम्भाव्य है, या

(ख) किसी मतदान केन्द्र से या को मतपेटियों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान, व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के मदद्यों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के प्रयोजन के लिए किसी यान, जलयान या पशु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सम्भाव्य है, तो राज्य सरकार, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या पशु का लिखित आदेश द्वारा अधिग्रहण कर सकेगी, और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगी जैसे अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या पशु, जिसे अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता, ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन से संसकन किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्वक उपयोग में ला रहा है, इस उप-धारा के अधीन तब तक



अधिगृहीत नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान सम्पन्न नहीं हो जाता।

(2) अधिग्रहण, राज्य सरकार द्वारा सम्पत्ति का स्वामी या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति समझे गए व्यक्ति को, सम्बोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा, और उस व्यक्ति पर जिसे वह सम्बोधित है, ऐसे आदेश की तामील विहित रीति में की जाएगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जब कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की जाती है, तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उप-धारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है।

(4) इस धारा में—

(क) "परिसर" से, कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है, और झोंपड़ी, शौड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत है;

(ख) "यान" से, ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो।

9-ख. प्रतिकर का संदाय.—(1) जब कभी राज्य सरकार, किसी परिसर को धारा 9-क के अनुसरण में अधिगृहीत करती है तब हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) परिसर की बाबत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए देय भाटक;

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति, परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिए विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हों):

परन्तु जहां कोई हितबद्ध व्यक्ति, ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम ने व्यथित होते हुए राज्य सरकार से, विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाए, वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम, ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां प्रतिकर पाने के हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बाबत कोई विवाद है, वहां अवधारण के लिए उसे राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगी और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पद से, वह व्यक्ति, जो धारा 9-क के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहित पूर्ण वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखना था, वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है।



(2) जब कभी राज्य सरकार कोई यान, जलयान या पशु, धारा 9-क के अनुसरण में अधिगृहीत करती है, तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जाएगा, जिसकी रकम का अवधारण राज्य सरकार ऐसे यान, जलयान या पशु को भाड़े पर लेने के लिए उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगी :

परन्तु जहां ऐसे यान, जलयान या पशु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए, राज्य सरकार से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाए, वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम, ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां अधिगृहीत किए जाने से अव्यवहित पूर्व, यान या जलयान, स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रम करार के आधार पर था, वहां अधिग्रहण के बारे संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उप-धारा के अधीन अवधारित रकम, उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिए वह सहमत हो जाए, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करे, प्रभाजित की जाएगी ।

9-ग. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति.—(1) जब धारा 9-क के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किए जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किए जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है, परिदत्त किया जाएगा, और कब्जे का ऐसा परिदान, राज्य सरकार को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में हैं, पूर्णतः, छनोचिन कर देगा, किन्तु उससे परिसर की बाबत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो ।

(2) जहां वह व्यक्ति, जिसे धारा 9-क के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उप-धारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, वहां राज्य सरकार यह घोषणा करने वाली सूचना, कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं, ऐसे परिसर के किसी सहजदृश्य भाग में लगवाएगी और सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

(3) जब उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है, तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अधीन, ऐसे प्रकाशन की तारीख की ओर से, न रहेंगे और उनकी बाबत यह समझा जाएगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिए गए हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और राज्य सरकार उक्त तारीख के पश्चात्, किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगी ।

9-घ. अधिग्रहण की बाबत राज्य सरकार के कृत्यों का प्रत्यायोजन.—राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उस सरकार पर,



धारा 9-क से लेकर धारा 9-ग तक के उपबन्धों में से किसी द्वारा प्रदत्त कोई शक्तियां या अधिरोपित कोई कर्तव्य, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे अधिकारी या ऐसे वर्ग के अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त या निर्वहित किए जाएंगे, जैसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

9-ड. कर्मचारिवृन्द की प्रतिनियुक्ति और शासकीय कर्तव्य के भंग पर दण्ड.—

(1) राज्य सरकार, सरकारी या राज्य सरकार के अर्ध-सरकारी संगठनों से, नगर निगम के सभी निर्वाचनों का संचालन करने के लिए, कर्मचारिवृन्द प्रतिनियुक्त करेगी और निर्वाचन नामावलियों को तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार तथा सभी निर्वाचनों के संचालन में नियोजित अधिकारी या कर्मचारिवृन्द उस अवधि के लिए जिसके दौरान वे इस प्रकार नियोजित किए जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग के नियन्त्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

(2) यदि उक्त उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचन ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त कोई व्यक्ति, निर्वाचन ड्यूटी के पालन से सम्बन्धित इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन का संचालन करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा करता है या जानबूझकर कर्तव्य से विमुख होता है अथवा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 13-क में,—

धारा 13-क  
का संशोधन।

(क) शीर्षक में “अधिकतम मात्रा” शब्दों के पश्चात्, “की सीमा” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) “अभिकर्ता” शब्द जहां कहीं आता है, के पश्चात् “या किसी अन्य व्यक्ति के प्राधिकार, सहमति या जानकारी” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

7. मूल अधिनियम की धारा 13-ख में, “अभिकर्ता ने” शब्दों के पश्चात् और धारा 13-ख “धारा 13-क” शब्द और अंकों से पूर्व “या किसी अन्य व्यक्ति के प्राधिकार, सहमति या जानकारी द्वारा” शब्द और चिन्ह, अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 13-ख  
का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) में “उपायुक्त” शब्द के स्थान पर, “राजस्व आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 का  
संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 14-क  
का अन्तः  
स्थापन।

“14-क. याचिका के पक्षकार.—कोई याची, याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल होगा,—

(क) जहां याची, घोषणा का दावा करने के अतिरिक्त कि सभी या किन्हीं निर्वाचित अभ्यर्थियों का निर्वाचन शून्य है, आगे ऐसी घोषणा का दावा करता है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है, याची



से भिन्न किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, और जहां आगे किसी घोषणा का दावा नहीं किया जाता है, सभी निर्वाचित अभ्यर्थी; और

(ख) कोई अन्य अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध याचिका में किसी भ्रष्ट आचरण के अभिकथन किए जाते हैं।”।

धारा 20 का संशोधन । 10. मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) में, “निदेशक” शब्द के लिए “वित्तायुक्त (अपील), हिमाचल प्रदेश सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, जैसा प्राधिकृत किया जाए, ऐसे अन्य अधिकारी” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन । 11. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(4-क). किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर, शत्रुता या घृणा की भावनाएं संप्रवर्तित करना या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करना।” ; और

(ख) उप-धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा :—

“(7-क). उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए, अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अथवा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति से, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में है, कोई सहायता अभिप्राप्त करना या उपाप्त करना अथवा अभिप्राप्त या उपाप्त करने का प्रयत्न या दुरुप्रेरण करना।”।

धारा 23 का संशोधन । 12. मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) उप-धारा (3) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।”।

धारा 24 का संशोधन । 13. मूल अधिनियम की धारा 24 में, उप-धारा (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टों की कालावधि के दौरान, किसी मतदान क्षेत्र में, कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई सार्वजनिक सभा न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें शामिल होगा या न उसे सम्बोधित करेगा; या



(ख) चलचित्र, टेलीविजन या उसी प्रकार के अन्य यन्त्र के द्वारा कोई निर्वाचन सामग्री, जन-साधारण को प्रदर्शित नहीं करेगा; या

(ग) उसमें लोगों को आकर्षित करने की दृष्टि से कोई संगीत समारोह या नाट्याभिनय अथवा कोई अन्य मनोरंजन या आमोद करके या उनको किए जाने का प्रबन्ध करने द्वारा, लोगों को किसी निर्वाचन सामग्री का प्रचार नहीं करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिन की अवधि दो वर्ष की हो सकेगी, या दस हजार रुपये से अधिक जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

**स्पष्टीकरण .—**इस धारा में, पद "निर्वाचन सामग्री" से, किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर या प्रभाव डालने के लिए आशयित या प्रकल्पित कोई सामग्री अभिप्रेत है।"

14. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

धारा 30 का संशोधन।

"(ज) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है।"

15. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 30-क, 30-ख, 30-ग, 30-घ, 30-ङ, 30-च, 30-छ, 30-ज, और 30-झ का अन्तःस्थापन।

"30-क. निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना.—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर सम्प्रवर्तित करता है या सम्प्रवर्तित करने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

30-ख. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव.—(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके सम्बन्ध में यह धारा लागू है, उस कारोबार के संबन्धित को निवारित करने के प्रयोजन के लिए, जिसके लिए यह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करता है या दूसरों को कार्य करने के लिए उदीप्त करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।



(3) यह धारा राजनैतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है, जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वालो, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच जिस को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है।

(4) यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की बाबत, युक्तियुक्त रूप से उप-धारा (1) के अधीन अपराध करने का सन्देह करता है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए, तो वह उस व्यक्ति से तुरन्त अपना नाम और पता बताने की अपेक्षा कर सकेगा, और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस अधिकारी, उसके द्वारा मिथ्या नाम या पता बताने का युक्तियुक्त रूप से सन्देह करता है तो, पुलिस अधिकारी उसे वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

30-ग. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निबन्धन .—(1) कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को —

(क) उस दशा में के सिवाय, न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित करवाएगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित द्विप्रतिक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है; और

(ख) उस दशा में के सिवाय, न तो मुद्रित करेगा या न मुद्रित करवाएगा, जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित—

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, जहां वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है; और

(ii) किसी अन्य दशा में, जिला जिसमें वह मुद्रित की जाती है, के जिला मजिस्ट्रेट को, दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया हेतु जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह मुद्रित



की गई समझी जाएगी और "मुद्रक" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ; और

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए विनष्ट कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विनिर्दिष्टियों को आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्चा सम्बन्धी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर, इसके अन्तर्गत नहीं है ।

(4) जो कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है, वह कारावास में, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

30-घ. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति.—यदि कोई निर्वाचक, जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा ।

30-ङ. निर्वाचनों में प्रवहनों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति, निर्वाचन में या निर्वाचन के संदर्भ में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है, जैसा इस अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

30-च. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति.—यदि सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

30-छ. मतदान केन्द्र को या उसके समीप सशस्त्र होकर जाने का प्रतिषेध.—  
(1) कोई भी व्यक्ति, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी और मतदान केन्द्र पर परिशान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति जो, मतदान केन्द्र में ड्यूटी पर है, से भिन्न, मतदान के दिन, मतदान केन्द्र के पड़ोस के भीतर किसी प्रकार के आयुध सहित, जैसा आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में यथापरिभाषित है, सशस्त्र होकर नहीं जाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।



(1) मायूम बाधितगण, 1950 (1950 का 54) में किसी बात के होने पर, यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध के लिए सिद्ध हो चुका है, उसके कब्जे में पाया जाने वाला, उक्त बाधितनियम में यथावर्णित मायूम, अधिदम्य किया जाएगा और वही ऐसे मायूम के सम्बन्ध में या यदि अनुमति उक्त बाधितनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसाहृत की गई समझी जाएगी।

(1) उपधारा (2) के अधीन कानूनी अपराध संज्ञित होगा।

30. मत्तदान के दिन कम्पोजिशा को सदाय सहित अवकाश दिन प्रदान किया जाएगा। (1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित और तत्पर निगम के निवासी या मन होने के हक्कार प्रत्येक व्यक्ति को, निर्वाचन के दिन मत्तदान पदान 'किया जाएगा'।

(2) उप धारा (1) के अनुसार दिए गए मत्तदान के कारण, ऐसे किन्हीं व्यक्तियों की मजदूरी से से कोई कहलेंगे या नहीं वही को जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आधार पर नियोजित है कि सत्तार-उत्त ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी प्राप्त नहीं करेगा, तो भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी सदा को जाएगी जिसको वह प्राप्त करता, यदि उस दिन के लिए उसे मत्तदान न दिया गया होता।

(3) यदि कोई निदेशक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा निदेशक जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुरस्थिति उक्त नियमों के अन्तर् में खतरा या भारवान् हानि कारित हो, जिसमें कि वह नगा हुआ है।

30. म. मत्तदान के दिन शराब न बेचना न देना या न वितरित करना.—(1) कोई भी स्थिति-युक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ, किसी भी मत्तदान क्षेत्र के भीतर, उस मत्तदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मत्तदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टों के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घण्टे की अवधि के दौरान, किसी होटल, खान-पान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में न बेचना, न दिया या न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है वह कान्वास में, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध हो चुका है, वहां उसके कब्जे में पाए गए स्थिति-युक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ अधिहरण किए जाएंगे और उनका निपटारा ऐसी रीति से किया जाएगा जैसी विहित की जाए।



## उद्देश्यों और कार्यों का कथन

संविधान (चौहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 का अधिनियमार्थ व संशोधन 1994 का हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया गया किन्तु संशोधन अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाईयों का अभाव नहीं था किन्तु वर्तमान निर्वाचित पदाधिकारियों की अवधि भई, 2002 के दौरान संपन्न हो रही है और निम्न में प्रत्येक निर्वाचन, पदाधिकारियों की अवधि की समाप्ति से पूर्व हो जाना अपेक्षित है किन्तु व अधिनियम अधिनियमित के दौरान व्यावहारिक कठिनाईयों का ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित संशोधन नग्न माने जायेंगे हैं।

जैसे कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में मण्डलायुक्त का पद समाप्त कर दिया गया है, इसलिए, इस अधिनियम के अधीन मण्डलायुक्त के कृत्यों को किसी अन्य प्राधिकारी को सम्पुर्णतः सौंप कर अन्तर्गत की गयी है। अब, यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन सम्पुर्णतः सौंपे के पक्ष पर करेगा। वर्तमान में, पार्षद के निर्वाचन का प्रावधान करने वाले निर्वाचन अधिनियम इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन, उपायुक्त को प्रस्तुत की जाती है, जबकि उपायुक्त, राज्य निगम के निर्वाचन के स्वयंसेवक प्रत्यक्षतः सम्मिलित है। इसलिए, उसके समक्ष निर्वाचन आचार्य को सौंपित करने सम्बन्धित नहीं है और राज्य उपायुक्त को इस शक्ति को भी देने का निश्चय किया गया है, और राज्य सरकार के द्वारा के द्वारा के द्वारा निर्वाचन के बजाय विन्तायुक्त (ग्रामीण), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चुने जायेंगे और पूर्णतः अधिनियम के आवश्यक उचित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

वर्तमान में यदि निर्वाचित अभ्यर्थी निर्वाचन के अवधि का संचालन नहीं देता है या निर्वाचन विफल होता है अथवा उसके दो में अधिक मुताबिक है, तो उसे निर्वाचन करने का कोई भी हक्क नहीं है जो यह निर्वाचन किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे निर्वाचन करने के लिए या निर्वाचन में निर्वाचन करने के निर्वाचन को जायेंगे।

अधिनियम में, निगम का निर्वाचन संचालित करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के सम्बन्धित को व्यवस्था करने का कोई उपबन्ध नहीं है। अब निगम के निर्वाचन का संचालन करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारियों, सामग्री और आर्थिक साधनों को व्यवस्था करने का निर्वाचन में सम्बन्धित करने का विनिश्चय किया गया है।

अधिनियम में निर्वाचन सम्बन्धी अथवा और निर्वाचन के संचालन के लिए अन्य कृत्यों को सम्बन्धित इत्यादि का अधिग्रहण करने के विषय में, उपबन्ध बनाए जाने सम्बन्धित है, क्योंकि ऐसे उपबन्ध अधिनियम में विद्यमान नहीं हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को पूर्ण के लिए है।

रजत रास, अध्यक्ष,  
प्रकारी मन्त्री।

शिमला :

.....2001.



### वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध विद्यमान संव द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे और कोई अनिश्चित व्यय नहीं होगा।

### प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 6 और 16 राज्य सरकार को, निर्वाचन के लिए परिसरों, गानों इत्यादि की अधीक्षण के लिए ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति पर, वह रीति जिसमें आदेश तामील किया जाएगा, की व्यवस्था करने और व्यक्ति के कब्जे में पाए गए अधिहृत स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थों का व्ययन करने की रीति के लिए भी व्यवस्था करने को सशक्त करते हैं।



*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

Bill No. 21 of 2001.

**THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION  
(AMENDMENT) BILL, 2001**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

**BILL**

*further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994  
(12 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in  
the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal  
Corporation (Amendment) Act, 2001.

Short title.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation  
Act, 1994 (hereinafter referred to as the “principal Act”), for the  
existing clause (14), the following clause shall be substituted,  
namely :—

Amend-  
ment of  
section 2.

“(14) “Revenue Commissioner” means the Revenue Commissioner  
of the Himachal Pradesh and includes any other officer appointed by  
the Government to perform all or any of the functions of the  
Revenue Commissioner under this Act;”

3. In section 8 of the principal Act, in sub-section (2),—

Amend-  
ment of  
section 8.

(a) after clause (d), the following shall be added, namely:—

“(dd) if he has incurred more expenditure than prescribed  
under section 13-A or has failed to lodge account  
under section 13-B within 30 days of the declaration  
of the result of the election;”

(b) in clause (e), the words “sentenced or” shall be deleted ;

(c) after clause (e), the following explanation shall be added,  
namely:—

“*Explanation.*—“moral turpitude” shall mean the cases where  
a charge framed by a competent court involves an offence



for which the maximum sentence is death or life imprisonment or 10 years or more;”;

- (d) in clause (k), for the word “or” appearing after the words “controlled by the Government”, but before the words “has been dismissed”, the sign “,” shall be substituted;
- (e) after clause (p), the following new clauses (q) and (r) shall be added, namely:—

“(q) if he has more than two living children:

Provided that the disqualification under clause (q) shall not apply to a person who has more than two living children on the date of commencement of Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2001, or, as the case may be, within a period of one year of such commencement, unless he begets an additional child after the said period of one year ; and

(r) if he has made any false statement or declaration in writing under this Act or the rules made thereunder.”.

Amend-  
ment of  
section 9.

4. In section 9 of the principal Act, in sub-section (2), after the words “the Commission such staff” but before the words “as may be necessary”, the sign and words “,material and monetary resources” shall be inserted.

Insertion  
of sections  
9-A, 9-B, 9-C,  
9-D and  
9-E.

5. After section 9 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely :—

“9-A. *Requisitioning of premises, vehicles etc. for election purposes.*—(1) If it appears to the State Government that in relation to the Municipal Corporation,—

- (a) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling station or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken, or
- (b) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election, the State Government, may by order in writing, requisition such premises, or such vehicle, vessel or animal, as the case may be, and may make such further orders as may appear to it to be



necessary or expedient in connection with the requisitioning :

Provided that no vehicle, vessel or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section until the completion of the poll at such election.

(2) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the State Government to be the owner or person in possession of the property and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-section (1), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-section.

(4) In this section,—

(a) "premises" means any land, building or part of building and includes a hut, shed or other structure or any part thereof; and

(b) "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise."

**9-B. Payment of compensation.**—(1) Whenever in pursuance of section 9-A, the State Government requisitions any premises, there shall be paid to the persons interested compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration the following, namely:—

(i) the rent payable in respect of the premises or if no rent is so payable, the rent payable for similar premises in the locality;

(ii) if in consequence of the requisition of the premises the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change:

Provided that where any person interested being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the State Government for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation, to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the State Government may determine :

Provided further that where there is any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of the amount of compensation, it shall be referred by the State Government to



an arbitrator appointed in this behalf by the State Government for determination, and shall be determined in accordance with the decision of such arbitrator.

*Explanation.*—In this sub-section, the expression “person interested” means the person who was in actual possession of the premises requisitioned under section 9-A immediately before the requisition, or where no person was in such actual possession, the owner of such premises.

(2) Whenever in pursuance of section 9-A, the State Government requisitions any vehicle, vessel or animal, there shall be paid to the owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the State Government on the basis of the fares or rates prevailing in the locality for the hire of such vehicle, vessel or animal :

Provided that where the owner of such vehicle, vessel or animal being aggrieved by the amount of compensation so determined make an application within the prescribed time to the State Government for referring the matter to an arbitrator the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the State Government may determine :

Provided further that where immediately before the requisitioning the vehicle or vessel was by virtue of hire-purchase agreement in the possession of a person other than the owner, the amount determined under this sub-section as the total compensation payable in respect of the requisition shall be apportioned between that person and the owner in such manner as they may agree upon, and in default of agreement, in such manner as an arbitrator appointed by the State Government in this behalf may decide.

**9-C. Release of premises from requisition.**—(1) When any premises requisitioned under section 9-A are to be released from requisition, the possession thereof shall be delivered to the person from whom possession was taken at the time when the premises were requisitioned, or if there were no such person, to the person deemed by the State Government to be the owner of such premises, and such delivery of possession shall be a full discharge of the State Government from all liabilities in respect of such delivery, but shall not prejudice any rights in respect of the premises which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom possession of the premises is so delivered.

(2) Where the person to whom the possession of any premises requisitioned under section 9-A is to be given under sub-section (1) cannot be found or is not readily ascertainable or has no agent or any other person empowered to accept delivery on his behalf, the State Government shall cause a notice declaring that such premises are released from requisition to be affixed on some conspicuous part of such premises and publish the notice in the Official Gazette.

(3) When a notice referred to in sub-section (2) is published in the Official Gazette, the premises specified in such notice shall cease



to be subject to requisition on and from the date of such publication and be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof; and the State Government shall not be liable for any compensation or other claim in respect of such premises for any period after the said date.

**9-D. Delegation of functions of the State Government with regard to requisitioning.**—The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any powers conferred or any duty imposed on it by any of the provisions of sections 9-A to 9-C shall, under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised or discharged by such officer or class of officers as may be so specified.

**9-E. Deputation of staff and punishment on breach of official duty.**—(1) The State Government shall depute staff from Government or Semi Government Organisations of the State Government for the conduct of all elections to the Municipal Corporation and the officers or staff employed in connection with the preparation, revision and correction of the electoral rolls for, and the conduct of all elections shall be deemed to be on deputation with the State Election Commission for the period during which they are so employed and such officers and staff shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the State Election Commission.

(2) If any person deputed on election duty under sub-section (1) disobeys any orders issued by an officer appointed to conduct the election under this Act regarding the performance of an election duty or deliberately abstains himself from duty or contravenes any provisions of this Act and the rules made thereunder, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.”

6. In section 13-A of the Principal Act,—

Amend-  
ment of sec-  
tion 13-A.

(a) in the heading after the word “maximum” but before the word “thereof”, the word “limit” shall be inserted; and

(b) after the words “election agent” wherever these occurs, the words and sign “or by any other person with his authority, consent or knowledge” shall be inserted.

7. In section 13-B of the principal Act, after the words “election agent” but before the words “under section”, the words and sign “or by any other person with his authority, consent or knowledge” shall be inserted.

Amend-  
ment of  
section 13-B.

8. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “Deputy Commissioner”, the words “Revenue Commissioner” shall be substituted.

Amend-  
ment of  
section 14.



Insertion  
of section  
14-A

9. After section 14 of the principal Act, the following new section 14-A shall be inserted, namely:—

“14-A. *Parties to the petition.*—A petitioner shall join as respondents to his petition,—

- (a) where the petitioner, in addition to claiming declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected, all the contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates; and
- (b) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petition.”.

Amendment  
of section  
20.

10. In section 20 of the principal Act, in sub-section (3), for the word “Director”, the words, brackets and signs “Financial Commissioner (Appeal) to the Government of Himachal Pradesh or such other officers, as may be authorised, by notification, by the State Government in consultation with the State Election Commission” shall be substituted.

Amendment  
of section  
21.

11. In section 21 of the principal Act,

- (a) after sub-section (4), the following shall be inserted, namely:—

“(4-A) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of citizens of India on grounds of religion, race, caste, community or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of candidate or his agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.”; and

- (b) after sub-section (7), the following shall be inserted, namely:—

“(7-A) The obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure by a candidate or his agent, or by any other person with the consent of the candidate or his agent, any assistance (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of that candidate's election, from any person in the service of the Government of India or any State or a local authority.”.



12. In section 23 of the principal Act, after sub-section (3), the following shall be added, namely:—

Amendment  
of section  
23.

“(4) An offence punishable under sub-section (3) shall be cognizable.”.

13. In section 24 of the principal Act, for sub-sections (2) and (3), the following shall be substituted, namely:—

Amendment  
of section  
24.

“(2) No person shall,—

- (a) convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election; or
- (b) display to the public any election matter by means of cinematography, television or other similar apparatus; or
- (c) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public thereto;

in any polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of poll for any election in that polling area.

(3) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine not exceeding rupees ten thousand, or with both.

*Explanation.*—In this section the expression “election matter” means any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election.”.

14. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (g), the following clause shall be added, namely:—

Amendment  
of section  
30.

“(h) violates the Model Code of Conduct issued by the State Election Commission.”.

15. After section 30 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:—

Insertion  
of sections  
30-A, 30-B,  
30-C, 30-D,  
30-E, 30-F,  
30-G, 30-H  
and 30-I.

“30-A. *Promoting animity between classes of citizen in connection with the election.*—Any person who in connection with an election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.



**30-B. *Disturbances at election meetings.***—(1) Any person who at a public meeting to which this section applies acts or incites others to act, in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was called together, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

(2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

(3) This section applies to any public meeting of a political character held in any constituency between the date of the issue of a notification under this Act calling upon constituency to elect a member or members and the date on which election is held.

(4) If any police officer reasonably suspects any person of committing an offence under sub-section (1), he may, if requested so to do by the Chairman of the meeting require that person to declare to him immediately his name and address and, if that person refuses or fails to declare his name and address, or if the police officer reasonably suspects him of giving a false name or address, the police officer may arrest him without warrant.

**30-C. *Restrictions on the printing of pamphlets, posters etc.***

(1) No person shall print or publish, or cause to be printed or published, any election pamphlet or poster which does not bear on its face the names and addresses of the printer and the publisher thereof.

(2) No person shall print or cause to be printed any election pamphlet or poster .

(a) unless a declaration as to the identity of the publisher thereof, signed by him and attested by two persons to whom he is personally known, is delivered by him to the printer in duplicate; and

(b) unless within reasonable time after the printing of the document, one copy of the declaration is sent by the printer, together with one copy of the document,—

(i) where it is printed in the Capital of the State, to the State Election Commission; and

(ii) in any other case, to the District Magistrate of the district, it is printed.

(3) For the purposes of this section,—

(a) any process for multiplying copies of a document, other than copying it by hand, shall be deemed to be printed and the expression “printer” shall be construed accordingly; and

(b) “election pamphlet or poster” means any printed pamphlet, hand-bill or other document distributed for the purpose of promoting or prejudicing the election of a candidate or group of candidates or any placard or poster having reference to an election, but does not include any hand-bill, placard or poster



merely announcing the date, time, place and other particulars of an election meeting or routine instructions to election agents or workers.

(4) Any person who contravenes any of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

**30-D. Penalty for failure to observe procedure for voting.**—If any elector to whom a ballot paper has been issued, refuses to observe the procedure prescribed for voting, the ballot paper issued to him shall be liable for cancellation.

**30-E. Penalty for illegal hiring or procuring of conveyance at elections.**—If any person is guilty of any such corrupt practices as specified in sub-section (5) of section 21 of this Act, at or in connection with an election, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three months, or with fine.

**30-F. Penalty for Government servants for acting as election agent, polling agent or counting agent.** If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at an election, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

**30-G. Prohibition of going armed to or near a polling station.**

54 of 1959

(1) No person, other than the returning officer, the presiding officer, any police officer and any other person appointed to maintain peace and order at a polling station who is on duty at the polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined in the Arms Act, 1959, of any kind within the neighbourhood of polling station.

(2) If any person contravenes the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

54 of 1959

(3) Notwithstanding anything contained in the Arms Act, 1959, where a person is convicted of an offence under this section, the arms as defined in the said Act found in his possession shall be liable to confiscation and the licence granted in relation to such arms shall be deemed to have been revoked under section 17 of that Act.

(4) An offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable.

**30-H. Grant of paid holiday to employees on the day of poll.**—(1) Every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at election to the Municipal Corporation shall, on the day of poll, be granted a holiday.

(2) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (1) and if such person is employed



on the basis that he would not ordinarily receive wages for such a day, he shall nonetheless be paid for such day the wages he would have drawn had not a holiday been granted to him on that day.

(3) If an employer contravenes the provisions of sub-section(1) or sub-section (2), then such employer shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(4) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

**30-I. *Liquor not to be sold, given or distributed on polling day.***—(1) No spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, catering house, tavern, shop or any other place, public or private, within a polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

(3) Where a person is convicted of an offence under this section, the spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature found in his possession shall be liable to confiscation and the same shall be disposed off in such manner as may be prescribed.”.



## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Consequent upon the enactment of the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 was enacted on 18th October, 1994. But practical difficulties in the implementation of certain provisions of the Act have been noticed from time to time. The term of the present elected office bearers of the Corporation is going to expire during May, 2002 and the next general election to the Corporation is required to be held before the expiry of the term of the office bearers. Keeping in view the practical difficulties faced during the last general elections of the Corporation, following amendments are required to be brought.

As the post of the Divisional Commissioner in the State has been abolished by the State Government, therefore, it has become necessary to assign the functions of the Divisional Commissioner under this Act to some other Authority. Now, it has been decided that Revenue Commissioner should perform the functions assigned under the Act. At present election petitions calling in question the election of a Councillor is presented to Deputy Commissioner under section 14 of this Act, whereas Deputy Commissioner is directly involved in the conduct of election to the Municipal Corporation. Therefore, it is not appropriate to file election petitions before him. Hence, it has also been decided to give this power to the Revenue Commissioner, and the appeals from the orders of Revenue Commissioner should be heard by the Financial Commissioner (Appeals) to the Government of Himachal Pradesh instead of Director. As such, necessary suitable amendments have been proposed in the Act *ibid*.

At present there is no provision to disqualify the elected candidate, if he does not lodge the account of expenditure of election or makes false statement, or have more than two children, hence it has been decided that such a candidate, should be disqualified for continuing as such or contesting election in future.

There is no provision in the Act to provide staff to the State Election Commission to conduct election of the Corporation. Now it has been decided to make provisions in the Act to provide staff, material and monetary resources to the State Election Commission to conduct the election of the Corporation.

Provisions regarding electoral offences and requisition of vehicles, buildings and premises etc. for the conduct of election are required to be made in the Act as such provisions do not exist in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ROOP DASS KASHYAP,  
Minister-in-Charge.

SHIMLA :-

The....., 2001.



---

**FINANCIAL MEMORANDUM**

The provisions of this Bill shall be implemented by the existing machinery and there shall be no additional expenditure.

---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clauses 5 and 15 of the Bill empowers the State Government to make rules to provide for the manner in which the order for requisition of premises, vehicles etc. for election shall be served on the owner or person in possession of such property and also to provide for the manner of disposal of the confiscated spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substance of a like nature found in possession of a person. These delegations are essential and normal in character.